माननीय न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लार के समक्ष

हरियाणा राज्य-अपीलकर्ता

बनाम

ईश्वर सिंह—प्रतिवादी

सीआरए संख्या 1012-एसबीए ऑफ 2000

जनवरी 8,2013

भारतीय दंड संहिता, 1860 - Ss.306, 498-A - 'आत्महत्या करने के लिए उकसाना' - अभियुक्त की पत्नी ने आत्महत्या की - अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 306 और 498-ए के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया - ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत बरी कर दिया और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया - बरी करने के खिलाफ राज्य की पसंदीदा अपील - अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की - अभियुक्त, अभियुक्त को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता - साजिश के सबूत और सक्रिय रूप से आत्महत्या के लिए उकसाना - दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की ऐसे आपराधिक मामलों का निर्णय करते समय सभी ठोस मूलभूत सिद्धांतों और आपराधिक कानून/न्यायशास्त्र के बुनियादी नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनमें से कुछ यह हैं कि किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष पर होती है। वही अभियुक्त को संभवतः बिना किसी ठोस सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के बावजूद आपराधिक कार्यवाही में सबूत आवश्यक तत्व हैं। यदि आपराधिक कार्यवाही के लिए अपराध के सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। यह कानूनी साक्ष्य है, जिसके आधार पर, एक आपराधिक अदालत का निर्णय आधारित है और आपराधिक न्याय की कानूनी आवश्यकता है। अन्यथा, ठोस ठोस साक्ष्य के अभाव में, न्यायालयों के पास बरी करने का आदेश दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो।

(पैरा 10)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा एक कार्य करने

के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पष्ट मेन्स री, सक्रिय भागीदारी या प्रत्यक्ष कार्य और इरादा होना चाहिए, जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प नहीं देखते हुए आत्महत्या कर ली और इस अधिनियम का उद्देश्य मृतक को ऐसी गंभीर स्थिति में धकेलना चाहिए कि उसने आत्महत्या कर ली, ज्ञान, इरादा, मासिक धर्म, सकारात्मक सक्रिय भागीदारी कोई विकल्प नहीं छोड़ना और किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व हैं।

(पैरा 17)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की पक्षकारों के विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, यह हित में होगा और न्याय की सेवा की जाएगी यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता दोषी को दी गई कारावास की सजा को कम किया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों पर: -

i) इस मामले में घटना 15.11.1998 की है और वह पहले ही पीड़ित है और लंबे समय तक मुकदमे और अपील के दर्द का सामना कर चुका है। पिछले 14 साल से अधिक।

ii) उसकी 75 वर्ष की बूढ़ी माँ है। वह क्षय रोग से पीड़ित थी।

iii) उसने अपने पिता को खो दिया है।

iv) उसके दो भाई सेना में हैं। अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

v) वह जमानत पर है।

vi) हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता दो साल के कारावास की कुल सजा में से कई महीनों तक अपनी मूल सजा की अवधि काट चुका है।

vii) वह प्रथम अपराधी है और वर्तमान वैवाहिक विवाद को छोड़कर पूर्व दोषी नहीं है।

(पैरा 28)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की रिकॉर्ड से उत्पन्न तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दो साल की कैद की सजा को घटाकर उसके द्वारा पहले से ही दस महीने कर दिया गया है।

(पैरा 29)

गौरव वर्मा, ए.ए. अपीलकर्ता-राज्य के लिए जी हरियाणा।

अपीलकर्ता-दोषी के वकील नवीन गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के.

न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लार, जे (मौखिक)

1. चूंकि कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, मैं पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस सामान्य निर्णय के माध्यम से, उसी आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न होने वाली संकेतित अपीलों का निपटान करने का प्रस्ताव करता हूं।

2. तथ्यों और सबूतों का मैट्रिक्स, परीक्षण के दौरान सामने आया, जिसकी परिणति प्रारंभ में हुई, तत्काल अपील पर निर्णय लेने और रिकॉर्ड से निकलने के लिए प्रासंगिक यह है कि, अपीलकर्ता दोषी ईश्वर सिंह का विवाह अप्रैल, 1989 के महीने में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार श्रीमती मंगी देवी (मृतक) के साथ हुआ था। विवाह के संपन्न होने के बाद, वे एक साथ रहते थे और पति और पत्नी के रूप में सहवास करते थे। उनका पहला बच्चा बेटा था, जो उसके जन्म के कुछ समय बाद ही मर गया था। इसके बाद, दो बेटियों का जन्म हुआ, जो घटना के समय क्रमशः छह साल और छह महीने की थीं। कहा जाता है कि गहने और प्रथागत उपहारों सहित पर्याप्त दहेज की वस्तुएं, मृतक के माता-पिता द्वारा शादी के समय और बेटियों के जन्म की पूर्व संध्या पर दी गई थीं, लेकिन अपीलकर्ता-दोषी संतुष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि वह बेटे के बजाय दो बेटियों को जन्म देने के लिए मृतक को ताना मारता था, परेशान करता था और पीटता था। अंततः श्रीमती मंगी देवी को ससुराल से बाहर कर दिया गया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला आगे बढ़ता है कि 15.11.1998 की रात को अपीलकर्ता-दोषी का भाई अमृत सिंह शिकायतकर्ता रणधीर सिंह (पीडब्लू 6) के घर गया

था और उसे बताया था कि उसकी बहन श्रीमती मंगी देवी ने कुछ जहरीली गोलियां खा ली थीं। उसे टोहाना के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने के बाद, शिकायतकर्ता और उसके भाई सेवा सिंह पहुंचे और "अस्पताल में मंगी देवी का शव पड़ा देखा। कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि अपीलकर्ता-दोषी द्वारा उसके जीवन को दयनीय बना दिया गया था

4. कई तरह के आरोप लगाते हुए और घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करते हुए, अभियोजन पक्ष के अनुसार कि अपीलकर्ता-दोषी ने श्रीमती मंगी देवी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इन आरोपों की पृष्ठभूमि में और शिकायतकर्ता की शिकायत के मद्देनजर, अपीलकर्ता-दोषी के खिलाफ एफआईआर संख्या 361 दिनांक 16.11.1998 के तहत पुलिस स्टेशन सिटी टोहाना, जिला हिसार की पुलिस द्वारा धारा 306 I पीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

5. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (चालान) सौंपी। तदनुसार, अपीलकर्ता-दोषी को ट्रायल कोर्ट द्वारा संकेतित अपराध करने के लिए आरोप-पत्र दिया गया था और मामले को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था।

6. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता-दोषी के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए, पीडब्लू 1 डॉ विनोद गुप्ता, पीडब्लू 2 डॉ अश्विनी कुमार, पीडब्लू 3 रंजोर सिंह कांस्टेबल, पीडब्लू 4 ओम प्रकाश एचसी, पीडब्लूएस छतर पाल सिंह, एमएचसी, पीडब्लू 6 शिकायतकर्ता रणधीर सिंह, पीडब्लू 7 लखमी चंद, पीडब्लू 8 गुलशन कुमारएएसआई और पीडब्लू 9 सीता राम पटवारी से मौखिक साक्ष्य में पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने पुलिस के आवेदन (पूर्व पीडी), पोस्टमार्टम के लिए आवेदन (पूर्व पीई / पीएफ), रफ साइट प्लान (Ex.PN), रिपोर्ट के संबंध में पुलिस का आवेदन (पूर्व पीएच), डॉक्टर (Ex.PH/1) की रिपोर्ट, सी. रंजोर सिंह (Ex.PK) का हलफनामा, एचसी छतर पाल सिंह (पूर्व.PL), रुक्का (पूर्व पीएम), पृष्ठांकन (Ex.PM/1), एफआईआर (Ex.PM/2), रिकवरी मेमो (एक्सपीओ) और पटवारी (Ex.PR) द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में तैयार की गई साइट प्लान।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अपीलकर्ता-दोषी का बयान दर्ज किया गया। पूरे दोषी ठहराने वाले सबूत को सबूतों में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के लिए रखा गया था, जैसा कि

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत विचार किया गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पूरी तरह से नकार दिया है और झूठे आरोप लगाए हैं। उसने बचाव की एक विशिष्ट लाइन अपनाई है कि उसने हमेशा अपनी पत्नी के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार किया और कभी भी उसे ताना नहीं मारा, परेशान नहीं किया और क्रूरता से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वह पेट के पुराने दर्द से पीड़ित थी और उसका इलाज किया गया था। वह अपनी बीमारी के कारण निराश हो गई और जहरीली गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। यह दावा किया गया था कि उसने जीवन बीमा पॉलिसी (Ex.DF) ली थी, जिसमें उसने अपनी मृत पत्नी को नामिती/लाभार्थी के रूप में नामित किया था। अपीलकर्ता-दोषी ने मृतक के चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड (पूर्व पीजी/1 से पूर्व पीजी *17) को भी रिकॉर्ड में लाया है।*

8. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता-दोषी को धारा 306 आई पीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए बरी कर दिया गया था। हालांकि, उसी समय, उसे दोषी ठहराया गया था और दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए और उसके चूक में, ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 498-ए आईपीसी के तहत एक साल की अवधि के लिए और कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 6.10.1999 की सजा और सजा के आदेश दिनांक 7.10.1999 थे।

9. इससे व्यथित होकर, हरियाणा राज्य ने धारा 3 06 आईपीसी के तहत बरी होने को चुनौती देने के लिए अपील (सीआरए नंबर 1012-एसबीए ऑफ 2000) को प्राथमिकता दी है, जबकि अपीलकर्ता-दोषी ने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने के लिए अलग अपील (1999 का सीआरए नंबर 978-एसबी) दायर की है। इस प्रकार मैं मामले से अवगत हूं।

10. सबसे पहले, जिस बात पर संभवतः विवाद नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि ऐसे आपराधिक मामलों का निर्णय करते समय सभी ठोस मूलभूत सिद्धांतों और आपराधिक कानून/न्यायशास्त्र के बुनियादी नियमों को ध्यान में रखना होगा। इनमें से कुछ यह हैं कि किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष पर होती है। अभियुक्त को संभवतः बिना किसी ठोस सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के बावजूद आपराधिक कार्यवाही में सबूत आवश्यक हैं। आपराधिक कार्यवाही के लिए अपराध के सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। यह कानूनी सबूत है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है

एक आपराधिक अदालत आधारित है और आपराधिक न्याय की कानूनी आवश्यकता है। अन्यथा, ठोस ठोस साक्ष्य के अभाव में, न्यायालयों के पास बरी करने का आदेश दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो।

11. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनकर, उनकी बहुमूल्य सहायता से अभिलेख का अध्ययन करने और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, वर्तमान अपीलों में कोई दम नहीं है।

12. प्रथम दृष्टया, राज्य के विद्वान वकील का तर्क कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि अपीलकर्ता-दोषी ने अपनी पत्नी मंगी देवी को ताना मारा, पिटाई की और क्रूरता के साथ व्यवहार किया और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, न तो मान्य है और न ही पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह और अन्य[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और *पंजाब राज्य बनाम* कश्मीर सिंह[2] के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियांइस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू होता है, जिसमें पति (उसमें) लगातार पत्नी से दहेज की मांग कर रहा था, उसे पीट रहा था, उसे परेशान कर रहा था और उसके लिए आतंक का माहौल बना रहा था। पत्नी ने अंततः खुद को और अपने तीन बच्चों को आग लगा दी। विशिष्ट तथ्यों और मामलों की विशेष परिस्थितियों में, यह फैसला सुनाया गया कि धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध बनता है।

13. संभवतः, पूर्वोक्त निर्णयों में निहित टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन, मेरे लिए, वर्तमान विवाद में राज्य के बचाव में यह नहीं आएगा।

14. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता-दोषी को उकसाने के अपराध के कमीशन के लिए आरोपित किया गया था। आईपीसी की धारा 306 में कहा गया है कि "यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दंडित किया जाएगा। किसी चीज के दुष्प्रेरण को आईपीसी की धारा 107 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए उकसाता है, जो किसी व्यक्ति को उस काम को करने के लिए उकसाता है; या उस चीज को करने के लिए किसी साजिश में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या

[1] (1991)3SCC 1
[2] 1994(3) RCR (Crl.) 538

व्यक्तियों के साथ संलग्न है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस चीज को करने के लिए; या जानबूझकर सहायता करता है, किसी भी कार्य या अवैध चूक से, उस काम को करना।

15. संक्षेप में, आईपीसी की धारा 108 यह मानती है कि एक व्यक्ति एक अपराध को बढ़ावा देता है, जो या तो अपराध करने के लिए उकसाता है, या एक कार्य के कमीशन जो एक अपराध होगा, अगर कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा उसी इरादे या ज्ञान के साथ अपराध करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि उकसाने वाले के समान इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है।

16. इन प्रावधानों के संयुक्त और सार्थक पठन से पता चलता है कि धारा 306 आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, रिकॉर्ड पर एक सकारात्मक सबूत होना चाहिए कि अपीलकर्ता ईश्वर सिंह ने जानबूझकर साजिश रची या वास्तव में / सक्रिय रूप से सहायता की और इस तरह से उकसाया, मंगी देवी के लिए आत्महत्या करने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

17. इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पष्ट मासिक धर्म, सक्रिय भागीदारी या प्रत्यक्ष कार्य और इरादा होना चाहिए, जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प नहीं देखकर आत्महत्या कर ली और इस कृत्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी गंभीर स्थिति में धकेलना होगा कि उसने आत्महत्या कर ली। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए ज्ञान, इरादा, मानसिक स्थिति, सकारात्मक सक्रिय भागीदारी और किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करना, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य तत्व हैं ।

18. इस प्रकार कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड पर सबूत होने के नाते, अब छोटा और महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन अपीलों में निर्धारण के लिए उठता है, यह है कि क्या अपीलकर्ता-दोषी, मंगी देवी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या या नहीं?

19. पक्षकारों के विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, चूंकि धारा 306 आईपीसी के सभी आवश्यक तत्वों का पूरी तरह से अभाव है और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 306 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया है ।

20. जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, कि अपीलीय अपराधी का विवाह अप्रैल, 1989 के महीने में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार श्रीमती मंगी देवी (मृतक) के साथ हुआ था। विवाह के संपन्न होने के बाद, वे एक साथ रहते थे और पति और पत्नी के

रूप में सहवास करते थे। उनका पहला बच्चा बेटा था, जो उसके जन्म के कुछ समय बाद ही मर गया था। इसके बाद, दो बेटियों का जन्म उनके विवाह से हुआ, जो छह साल और छह महीने की थीं। Thc पर्याप्त दहेज

कहा जाता है कि गहने और प्रथागत उपहार सहित लेख, शादी के समय और बेटियों के जन्म की पूर्व संध्या पर मृतक के माता-पिता द्वारा दिए गए थे। उसने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। यह तथ्य सिटी अस्पताल, टोहाना में मृतका का इलाज करने वाले पीडब्ल्यूआई डॉ. विनोद गुप्ता और शव का पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-2 डॉ. अश्वनी कुमार के मेडिकल साक्ष्य (Ex.PG) से साबित होता है। पीडब्लू 6 रणधीर सिंह और पीडब्लू 7 लखमी चंद ने भी अपने-अपने बयानों में ऐसा कहा है। इसके अलावा, पीडब्लू 6 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता-दोषी ने अपनी पत्नी मंगी देवी को पीटी बेटी के जन्म के बाद रक्तदान करने के लिए दो बोतल रक्त दान किया था। इतना ही नहीं, जीवन बीमा पॉलिसी (Ex.DP) में, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने नामांकित और लाभार्थी के रूप में नामित किया। इस प्रकार, विद्वान वकील की प्रस्तुति कि अपीलकर्ता का अपनी पत्नी के साथ प्यार और स्नेह था और उसने उसे रक्त दान किया, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज करता है और बचाव पक्ष के संस्करण को साबित करता है, काफी बल है।

21. इतना ही नहीं, पीडब्लू 6 और पीडब्ल्यू 7 के बयानों का तरीका मुख्य रूप से यह है कि अपीलकर्ता-दोषी ने मृतक को केवल इस कारण परेशान किया और उसका इलाज किया कि उसने दो बेटियों को जन्म दिया और एक बेटा पैदा करने में विफल रही। यदि उनके पूरे बयानों को एक साथ रखा जाए और तर्क के लिए उन्हें सच माना जाए, तो भी उनके बयानों से जो साबित होता है वह यह है कि मांगी देवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। उसे ससुराल से निकाल दिया गया। हालांकि, रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसके द्वारा आत्महत्या करने के छह महीने की अवधि के भीतर दो बेटियों के जन्म के संबंध में उसके साथ इस तरह की क्रूरता की गई। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि कथित क्रूरता का अंतिम कृत्य उसकी मृत्यु से छह महीने पहले हुआ था।

22. रिकॉर्ड पर इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता-दोषी को कैसे, किस समय, कब और किस तरीके से ज्ञान, इरादा, मासिक धर्म था या वास्तव में संबंधित दिन पर मंगी देवी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था।

इसके विपरीत, यह रिकॉर्ड पर आया है कि मृतका अपने मेडिकल रिकॉर्ड (Ex.PG/1 से Ex.PG/7) के अनुसार पेट दर्द की पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। इली अपीलकर्ता-दोषी ने उसे रक्त दान किया। इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी (Ex.DF) में, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने नामांकित और लाभार्थी के रूप में नामित किया। पीडब्लू 6 और पीडब्ल्यू 7 द्वारा अनुमानित कथित क्रूरता का अंतिम कार्य वर्तमान घटना से छह महीने पहले का है। इन परिस्थितियों में चूंकि आईपीसी की धारा 306 के सभी आवश्यक तत्व गहराई से गायब हैं, इसलिए, यह संभवतः नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता-दोषी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए, मेरे विचार से विचारण न्यायालय ने उन्हें धारा 3061 के तहत अपराध करने के लिए बरी कर दिया है। 'राज्य के वकील ने इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के अच्छी तरह से व्यक्त फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी आधार/कारण को इंगित नहीं किया, बहुत कम ठोस।

23. अब अपीलकर्ता-दोषी की अपील का विज्ञापन करते हुए, रिकॉर्ड पर पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत हैं, जैसा कि यहां चर्चा की गई है, यह साबित करने के लिए कि उसने अपनी पत्नी मंगी देवी को मानसिक और शारीरिक क्रूरता के साथ ताना मारा, परेशान किया और उसके साथ व्यवहार किया। PW6 और PW7 ने इतना कहा है कि अपीलकर्ता दोषी द्वारा उसे कई बार ताना मारा गया, परेशान किया गया और पीटा गया और अंततः उसे वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया। रिकॉर्ड पर सबूत इस प्रासंगिक संबंध में विश्वसनीय और विश्वसनीय हैं।

24. इसलिए, यदि अभियोजन के पूरे साक्ष्य का अवलोकन किया जाता है और एक साथ रखा जाता है, तो मेरे विचार से यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 306 के तहत अपेक्षित सभी आवश्यक अवयवों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। हालांकि, साथ ही, इसने अपीलकर्ता-दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोप को विधिवत साबित कर दिया है। इसलिए, मेरे लिए, ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत बरी कर दिया है और उसे आईपीसी की धारा 498-ए के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

25. स्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए, विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वह अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए ठोस सबूतों के मद्देनजर आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपीलकर्ता-दोषी की सजा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा। चूंकि अपीलकर्ता-दोषी के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य कानूनी दुर्बलता नहीं बताई गई है, इसलिए, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और जुर्माने की सजा का आदेश मामले की प्राप्त परिस्थितियों में बनाए रखा जाना चाहिए।

26. हालांकि, विद्वान वकील का तर्क यह है कि चूंकि अपीलकर्ता की 75 वर्ष की बूढ़ी मां है और वह पूर्व दोषी नहीं है, इसलिए उसने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात को देखते हुए सजा की अवधि को कम करने की प्रार्थना की ***/ होशान और अन्य बनाम*** आंध्र प्रदेश राज्य[3] ***और कश्मीरी लाल*** बनाम ***हरियाणा राज्य***[4] के मामले में इस न्यायालय का ***/***

27. मैं पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के संबंध में कहना चाहता हूं, मेरे विचार से, यह अंतर्ज्ञान में होगा और यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता-दोषी

[3] AIR 2002 SC 3270
[4] 2008(4) RCR (Crl.)497

को दी गई कारावास की सजा को कम किया जाता है, तो अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों पर -

१) इस मामले में घटना 15.11.1998 की है और वह पहले ही पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से लंबे मुकदमे और पील के कष्टों का सामना कर चुके हैं।

२) झूठ की 75 साल की बूढ़ी मां है। वह क्षय रोग से पीड़ित थी।

iii) उसने अपने पिता को खो दिया है।

iv) उसके दो भाई सेना में हैं। 'अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

v) वह जमानत पर है।

vi) हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता दो साल के कारावास की कुल सजा में से दस महीने की अपनी मूल सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।

vii) वह प्रथम अपराधी है और वर्तमान वैवाहिक विवाद को छोड़कर पूर्व दोषी नहीं है।

29. उपरोक्त कारणों के आलोक में, चूंकि कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, राज्य और अपीलकर्ता-दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता-दोषी पर लगाए गए जुर्माने की सजा के आदेश को बरकरार रखा गया। हालांकि, रिकॉर्ड से निकलने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दो साल की कैद की सजा को घटाकर पहले से ही दस महीने कर दिया गया है। तदनुसार, वाक्य के आक्षेपित क्रम को उस सीमा तक और तरीके से संशोधित किया जाता है जैसा कि यहां-पहले दर्शाया गया है।

30. कहने की जरूरत नहीं है कि आवश्यक परिणाम और अनुपालन स्वाभाविक रूप से तदनुसार पालन करेंगे।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।